

प्रेषक,

आर० के० सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा, निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 31 मार्च, 2015।

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर के अन्तर्गत मढ़ी कालोनी चौरास परिसर में 200 बैड नर्सिंग हॉस्टल के निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 264/चि०शि०/154/2014/1304 दिनांक 10.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर के अन्तर्गत मढ़ी कालोनी चौरास परिसर में 200 बैड नर्सिंग हॉस्टल के निर्माण कार्य हेतु टी०ए०सी० वित्त एवं व्यय वित्त समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यापूर्ण/संस्तुत धनराशि रु० 977.29 लाख एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार धनराशि रु० 43.95 लाख इस प्रकार कुल रु० 1021.21 लाख (रु० दस करोड़ इक्कीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनगत पक्ष में प्राविधानित बजट में अवशेष रु० 10710000/- करोड़ एवं चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का भवन निर्माण मद संख्या 4210-03-105-14-24 में प्राविधानित धनराशि रु० 10.00 करोड़ में से पुनर्विनियोग के माध्यम से रु० 02.29 करोड़ संलग्न बी०एम० -09 (एक) के विवरणानुसार राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर की स्थापना मानक मद संख्या 4210-03-105-03 में पुनर्ग्रहीत करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार के विशेष योजनागत सहायता (SPA) के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर के अधीन मढ़ी कालोनी चौरास परिसर स्थित 200 बैड नर्सिंग हॉस्टल के कार्यों हेतु धनराशि ₹ 3,36,10,000.00 करोड़ (रु० तीन करोड़ छत्तीस लाख दस हजार मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में पुनर्ग्रहीत कर संगत मद में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष इतनी ही धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इस संबंध में समस्त प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाए जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।
6. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भूतली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
7. विस्तृत आगणन से प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए। कार्य की प्रगति की निरंतर व गहन समीक्षा करते हुये कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एमओयू अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा डीओएसओआर की दरों के आधार पर आगणन तैयार किया जा रहा है तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम अपने कार्य प्रदर्शिका, वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा डीओएसओआर के नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि त्रुटिवश कोई फाइनेशियल डुप्लीकेसी हुई हो तो उसका तत्काल निराकरण करेंगे।
10. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
11. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित करें।
17. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-राजकीय मेडिकल कालेज श्रीनगर की स्थापना के भ्रानक मद- 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
18. यह आदेश वित्त अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन के अशाओ सं0- 515(P)/XXVII(3)/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
19. उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति संबंधी ऑन लाइन बजट कम्प्यूटर अलोटमेंट आईओडी0 संख्या- SIS03121061 दिनांक- 31 मार्च, 2015 के अन्तर्गत की जा रही है।

संलग्नक-यथोपरि। SIS03121061

भवदीय,

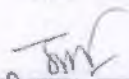
(आर0 के0 सुधांशु)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर गढ़वाल।
7. महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, श्रीनगर इकाई, श्रीनगर गढ़वाल।
9. बजट प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग-3/नियोजन विभाग/एनओआई0सी0, सचिवालय परिसर।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(जीओएन0 पन्त)
अनु सचिव।